जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 46 संख्याः 269 प्रभात बीकानेर, मंगलवार 22 अप्रैल, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

गहलोत सरकार का कोविड प्रबंधन उत्कृष्ट है: नये-नये तरीके ढूंढ़े गये चहेती कंपनियों से लूट मचवाने के लिए

उदाहरण के लिए, एसएमएस अस्पताल को अधिकृत किया गया, राज्य के सभी अस्पतालों के लिये वैंटीलेटर खरीदने के लिये

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 21 अप्रेल। गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान कोविड महामारी के चलते स्टेट डिज़ास्टर रिएक्शन फंड (एस.डी.आर.एफ.) से आई.सी.यू. इत्यादि जैसे स्थाई निर्माण ही नहीं किये गये, बल्कि चिकित्सा विभाग के वित्त सलाहकारों ने नियमों की अनदेखी करते हुए इन आई.सी.यू. व बच्चों के लिये बने एन.आई.सी.यू. और पी.आई.सी.यू. के निर्माण कार्यों को "टर्नकी" प्रोजेक्ट की तर्ज पर शुरू करने की अनुमति भी दे दी, जिसके कारण इन आई.सी.यू. में लगाये जाने वाले उपकरणों की खरीद में भी भारी धांधली हुई।

दरअसल कोविड महामारी के दौरान चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद पर केन्द्र सरकार ने टैक्स में भारी कटौती की थी, इसके तहत जी.एस.टी. 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई थी, परंतु यह छूट टर्नकी प्रोजेक्ट्स पर लागू नहीं की जा सकती। पर हैरानी की बात है कि एस.एम.एस मेडिकल कॉलेज की क्रय समिति ने पूरे प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में वेंटिलेटर, ई.सी.जी. मशीन, वॉर्मर इत्यादि खरीदे लेकिन महंगी दरों पर और सप्लायरों की तरफ से 12 प्रतिशत जी.एस.टी. भी अदा किया।

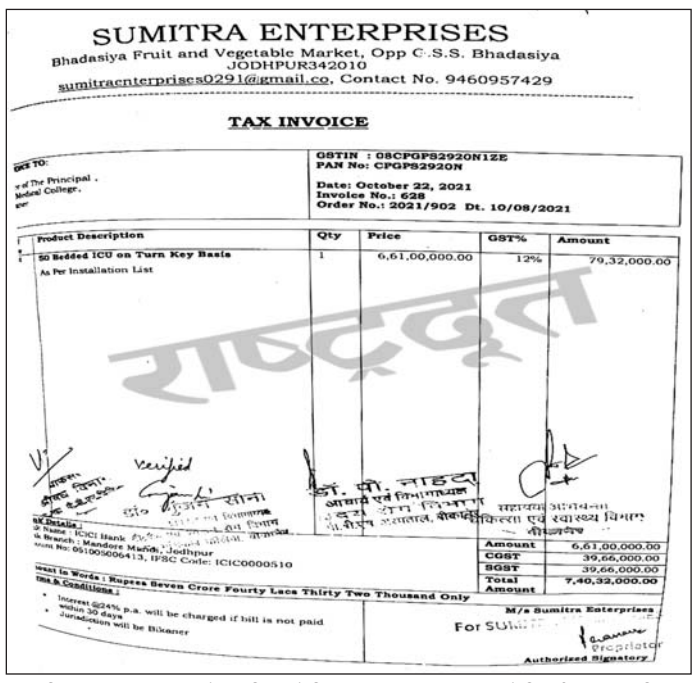

यही नहीं एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज की क्रय समिति ही पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के लिये मेडिकल उपकरण खरीद के आदेश दे रही थी, जबकि उन्हें किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ओर से उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव नहीं सौंपा गया था। हालांकि यह भी सत्य है कि महामारी के दौरान मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिये निविदा जारी नही की जा सकती थी, क्योंकि राजस्थान में लोक उपापन में पारदर्शिता (आर.टी.पी.पी.) अधिनियम निलंबित था। परंतु राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत मेडिकल उपकरणों की खरीद आर.एम.एस. सी.एल. के माध्यम से की जा सकती थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

SUMITRA ENTERPRISES

TAX INVOICE

Amount	6,61,00,000.00
CGST	39,66,000.00
SGST	39,66,000.00
Total Amount	7,40,32,000.00

Amount in Words : Rupees Seven Crore Fourty Lacs Thirty Two Thousand Only

Terms & Conditions :
- Interest @24% p.a. will be charged if bill is not paid within 30 days
- Jurisdiction will be Bikaner

M/s Sumitra Enterprises

Authorized Signatory

प्रकाशित दस्तावेज एक टैक्स बिल है जिसमें देखा जा सकता है कि बीकानेर मेडिकल कॉलेज में सुमित्रा एन्टरप्राइजेज नामक एक फर्म से 50 बिस्तर के आई.सी.यू. में "टर्नकी प्रोजेक्ट" के माध्यम से मेडिकल उपकरणों को लगाने का अनुबंध किया गया था। इस कंपनी द्वारा मेडिकल उपकरण लगाने के लिये मेडिकल कॉलेज से 12 प्रतिशत की दर पर जी.एस.टी. वसूला गया। जैसा कि विदित है कि कोविड के दौरान केंद्र सरकार ने मेडिकल उपकरणों की खरीद पर जी.एस.टी. की दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी थी, परंतु गहलोत सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नियम और नीति के विरूद्ध जाते हुए एस.डी.आर.एफ. से घटिया दर्जे के आई.सी.यू. का निर्माण कराया और मेडिकल उपकरण की खरीद में भी भारी धांधली की।

- पर, किस अस्पताल को कितने वैंटीलेटर चाहिए अपने आईसीयू के लिए, इस बारे में अस्पतालों से न तो पूछा गया और न ही कोई बातचीत की गई।
- जैसा कि खबर के साथ प्रस्तुत बिलों की प्रतियों से नज़र आता है। एसएमएस अस्पताल के लिये जिन दामों पर वैंटीलेटर खरीदे गये, उससे लगभग दोगुने दामों पर प्रदेश के अन्य अस्पतालों के लिए वैंटीलेटर खरीदे गयें, यह एक्स्ट्रा पेमेंट किस को मिला?
- वैंटीलेटर सप्लाई करने वाली कंपनी को जीएसटी का पूरा लाभ दिलाने की दृष्टि से वैंटीलेटर केन्द्रीय सरकार की नीति व आपदा प्रबंधन निधि से खरीददारी नहीं की गई। अगर केन्द्रीय सरकार की व्यवस्था के अनुसार खरीद की जाती तो जीएसटी 12 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत ही लगती। ऐसे "सुप्रबंधन" के कई नायाब तरीके ढूंढ़े गये और सप्लायर को लाभान्वित किया।
- गहलोत सरकार के अधिकारी कुछ गिनी चुनी कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मेडिकल उपकरणों की खरीद का बल्क ऑर्डर ना देके अलग-अलग खरीद के आदेश पारित कर रहे थे। इसका स्पष्ट प्रमाण एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज की क्रय समिति और बीकानेर के एस पी मैडिकल कॉलेज की क्रय समिति के वित्तीय सलाहकारों की कार्य प्रणाली पर कई सवाल उठते हैं। जहां एक ओर वेंटिलेटर 9 लाख रुपये की दर पर खरीदे गये वहीं दूसरी ओर लगभग दुगनी लागत पर खरीदे गये।

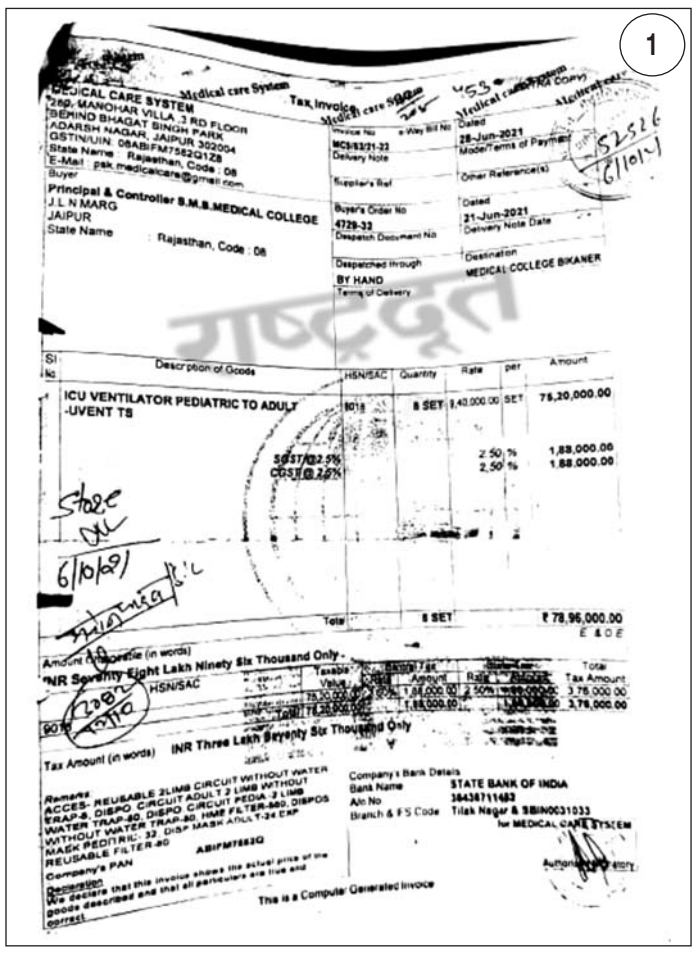

1

ICU VENTILATOR PEDIATRIC TO ADULT

STATE BANK OF INDIA

लालू-राबड़ी व नीतीश का युग समाप्ति की ओर अग्रसर

नई पीढ़ी के नेता, भाजपा के सम्राट चौधरी, आरजेडी के तेजस्वी के साथ-साथ चिराग पासवान व प्रशांत किशोर को भी नये समीकरणों की राजनीति में अपना महत्व बढ़ने की संभावना दिख रही है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अप्रैल। केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान "बिहार मुझे बुला रहा है" ने एनडीए पार्टनरों, जिनमें भाजपा और जेडीयू शामिल हैं, के कान खड़े कर दिये हैं।

अपने स्वर्गीय पिता के विपरीत, जूनियर पासवान ने राज्य की राजनीति में कूदने की अपनी अंदरूनी इच्छा के संकेत कई बार दिये हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वघोषित "हनुमान" के रूप में, उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए पार्टनर जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किये थे। उन्होंने यह कदम उठाकर, राज्य विधानसभा में नीतीश कुमार की जेडीयू के सदस्य संख्या बहुत कम कर दी थी तथा जेडीयू, भाजपा और आरजेडी के बाद, तीसरे नम्बर पर रही थी।

पिछले तीन दशकों तक, लालू-राबड़ी तथा नीतीश के शासन के लंबे दौर के बाद, ऐसी संभावना हो सकती है कि आगामी चुनावों के बाद, बिहार में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- चिराग पासवान ने अपने बारे में नया नारा, "बिहार बुला रहा है" देकर अपना मन्तव्य और स्पष्ट कर दिया है। चिराग मान रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव की भांति, भाजपा उनका "उपयोग" करना चाहेगी, नीतीश कुमार के राजनीतिक कद को नियंत्रित रखने के लिए।
- पिछले चुनाव में चिराग ने नीतीश की पार्टी के सभी उम्मीदवारों के सामने अपने उम्मीदवार खड़े किये थे तथा नतीजा यह निकला था कि नीतीश की पार्टी के कई उम्मीदवार चुनाव हार गये थे, हालांकि, नीतीश ने भी भाजपा जितनी सीटें पाई थीं, सीटों के बंटवारों के समय।
- नीतीश की पार्टी विधायकों की संख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर पहुँची, भाजपा व आरजेडी के बाद।

पोप फ्रांसिस का निधन

वेटिकन, 21 अप्रैल। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का ईस्टर सोमवार को वेटिकन के कासा सांता मार्टा में उनके निवास पर निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। होली सी (रोमन कैथलिक चर्च की सरकार) ने आज यह जानकारी दी। होली सी ने एक्स पर लिखा, पोप फ्रांसिस का निधन ईस्टर सोमवार को 88 वर्ष की आयु में वैटिकन के कासा सांता मार्टा में उनके निवास पर हुआ। वैटिकन के मुताबिक स्थानीय समयानुसार सुबह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- 88 वर्षीय पोप फ्रांसिस ने वैटिकन के कासा सांता मार्टा में अपने निवास पर अंतिम सांस ली।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा से हिन्दुस्तान के लिए खिड़की तो खुली, ट्रम्प तक बात पहुँचाने के लिए

इस समय अमेरिका, यूरोपियन यूनियन व चीन, दोनों से "लगभग" शत्रुता के रिश्ते बनाये हुए है और बातचीत बंद सी है। अतः भारत के पास अपना पक्ष सुनाने का अच्छा मौका है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अप्रेल। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस की आज की भारत यात्रा, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देती है।

सबसे पहले, इस यात्रा में एक व्यक्तिगत पहलू है, जो उनकी पहली यात्रा के बारह साल बाद हो रही है। इस व्यक्तिगत जुड़ाव के बयान के साथ, वैंस की भारत यात्रा इस बात को स्पष्ट करती है कि वर्तमान वैश्विक परिपेक्ष्य में भारत अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

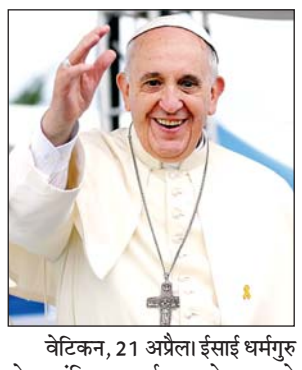

यह बात भी महत्वपूर्ण है कि भारत में अपने शुरुआती कार्यक्रमों के तहत, उपराष्ट्रपति ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया, जहाँ वैंस के बच्चों ने भारतीय परिधान पहन रखे थे और उनके गले में फूलों की मालाएँ थीं। इससे अमेरिका की "सैकण्ड फैमिली" और भारत के बीच सांस्कृतिक और व्यक्तिगत संबंधों का गहरा संकेत मिला।

दूसरा संकेत मिला कि भारत, अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश को एशिया में तथा समग्र भू-राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध एक मजबूत दीवार के रुप में देखा जाता है। अमेरिका चीन को अपना प्रमुख प्रतिद्वंद्वी मानता है, आर्थिक रुप से भी और रणनीतिक संतुलन के लिहाज से भी।

गौरतलब है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समय दक्षिण -पूर्वी एशिया के एक लंबे दौरे पर हैं, जहाँ वे एक ऐसा राष्ट्र-गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अमेरिका के विरुद्ध चीन के साथ खड़ा हो सके। अभी हाल तक, दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश लगभग अमेरिका के सहयोगी देश ही माने जाते थे।

अब चीन इन देशों को, चीन के विशाल बाज़ारों में आकर्षक सुविधाओं का लालच देकर अमेरिका से दूर करने की कोशिश कर रहा है। चीन इन देशों को यह दिखाना चाहता है कि अमेरिका की तुलना में वो कहीं ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर है। इस तरह से, चीन एशिया में, और अन्य जगहों पर भी, अमेरिका को उसके सहयोगियों से अलग-थलग करने की कोशिश कर रहा है।

कई मायनों में, अमेरिका पहले से ही वैश्विक मंच के प्रमुख खिलाड़ियों से थोड़ा अलग-थलग हो गया है। ट्रंप प्रशासन ने चीन और यूरोपीय संघ, जो आर्थिक और रणनीतिक रुप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्लॉक हैं, को बुरी तरह आहत किया है।

वैंस बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ैलेंस्की के साथ डॉनल्ड ट्रंप की कुख्यात बैठक में भी उनकी प्रमुख भूमिका थी। वैंस, ट्रंप के विश्वासपात्र हैं, हालांकि, ट्रंप अपनी मर्जी के मालिक हैं। हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान वैंस को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था।

इस प्रकार, भारत के पास यह अवसर है कि वह अमेरिका को अपनी स्थिति समझा सके, खासकर ऐसे समय में, जब अमेरिका ने अपनी टैरिफ की बाढ़ के जरिए प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ एक प्रकार का व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। भारत को भी तथाकथित "रैसिप्रोकल टैरिफ" का सामना करना पड़ा है, जिसे वर्तमान में 90 दिनों के लिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- पर, जैसा ट्रम्प का स्वभाव है, अगर इनमें से किसी से भी बातचीत शुरु हुई तो ट्रम्प भारत का साथ छोड़कर, इन दोनों से सौदेबाजी शुरु कर देंगे, क्योंकि अपने साइज़ व आर्थिक ताकत के कारण, ये दोनों भारत से ज्यादा महत्व रखेंगे, ट्रम्प की निगाह में।

जेल प्रहरी पेपर लीक के आरोपी को जमानत नहीं मिली

जयपुर, 21 अप्रैल। जयपुर मेट्रो-प्रथम की डीजे कोर्ट ने जेल प्रहरी भर्ती-2018 के पेपर लीक मामले के आरोपी करन कुमार को जमानत देने से इनकार करते हुए, आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। डीजे नंदिनी व्यास ने फैसले में कहा कि मौजूदा मामले में आरोपी को लंबे समय से अनुसंधान के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। उसकी तलाश के लिए कई जगहों पर दबिश दी गई, जिस कारण केस के अनुसंधान में भी देरी हुई है। मामला सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम व अन्य गंभीर अपराधों से जुड़ा है और ऐसे मामले के आरोपी को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अदालत ने कहा, आरोपी लंबे समय से अनुसंधान के लिये उपस्थित नहीं हो रहा है, इसलिये जमानत नहीं दी जा सकती।

'वैंस की भारत यात्रा से हिन्दुस्तान की टैरिफ संबंधी चिंताएँ घटेंगी नहीं'

चीन के प्रमुख समाचार पत्र, ग्लोबल टाइम्स तथा चीन के नैशनल स्ट्रेटेजी इन्स्टीट्यूट का मानना है, दोनों देशों की वाणिज्य नीतियों में सामंज़स्य बैठना संभव नहीं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अप्रेल। क्या अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस की भारत यात्रा से वॉशिंगटन की टैरिफ नीति पर नई दिल्ली की चिंताएँ कम होंगी? बीजिंग का कहना है, ऐसा नहीं होगा। बीजिंग ने यात्रा के परिणामों और उद्देश्यों को बहुत हल्के रूप में लिया है।

चीन के ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के अनुसार, वैंस की चार दिवसीय भारत यात्रा दोनों देशों के बीच के आर्थिक अवसरों को अनलॉक करने और द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों के बीच हुई है। लेकिन भारत और चीन के विश्लेषक इस बात पर सहमत हैं कि इस यात्रा से अमेरिका के कथित "रैसिप्रोकल टैरिफ" पर भारत की चिंताओं में कोई राहत नहीं मिलेगी और न ही इससे भारत की व्यापार नीति में कोई निर्णायक बदलाव होगा।

अपनी अधिकृत कूटनीति को "पर्सनल टच" देते हुए, वैंस अपनी पत्नी ऊषा वैंस, जो हिंदू हैं और बच्चों के साथ भारत आए हैं। उनके साथ अमेरिकी प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं। ये सभी दिल्ली, जयपुर और आगरा जाएंगे तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इन्हें एक रात्रिभोज देंगे। संभावना है कि वार्ता का फोकस लम्बे समय से विचाराधीन ट्रेड पैक्ट होगा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के नए मुकाम तलाश करने पर होगा। वैंस के साथ अमेरिका के 5 टॉप अधिकारी हैं, जिनमें पैंटागन और विदेश विभाग के अधिकारी शामिल हैं।

यह वैंस की पहली भारत यात्रा है और चीनी पर्यवेक्षक इसके रणनीतिक संकेतों के बारे में बात करते हुए कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। विशेषज्ञों का मत है कि यह यात्रा सावधानीपूर्वक तैयार की गई सोची समझी रणनीति है, जिसमें कूटनीति और पारिवारिक जुड़ाव का मिश्रण है और इसका उद्देश्य टैरिफ के कारण यूएस के अपने सहयोगियों के साथ उपजे तनाव के समय में भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करना है, लेकिन बीजिंग में कुछ ही विशेषज्ञ मानते हैं कि यह यात्रा भारत को अनसुलझे टैरिफ विवाद से राहत देगी।

शिन्हुआ विश्वविद्यालय के नैशनल स्ट्रैटजी इंस्टीट्यूट के निदेशरक कियान फेंग का कहना है कि वैंस कई उद्देश्यों पर काम कर रहे हैं। द्विपक्षीय ट्रेड पैक्ट से लेकर टैरिफ विवादों के हल तक पर फेंग ने चेतावनी दी कि ठोस नतीजे मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि वॉशिंगटन का सारा जोर व्यापार घाटा कम करने और निर्माण गतिविधियों को अमेरिका वापस लाने पर है। यह रणनीति "मेक इन इंडिया" के खिलाफ है।

हालांकि, कुछ प्रगति हुई है, जैसे 29 मार्च को अमेरिका के ट्रेड प्रतिनिधियों व भारत के वाणिज्य मंत्रालय के बीच 2030 तक व्यापार 500 बिलियन डॉलर पहुँचाने के लक्ष्य पर समझौता हुआ, पर अभी भी कई बाधाएं हैं।

इस पृष्ठभूमि में विश्लेषकों का कहना है कि वैंस संभवतः भारत को वॉशिंगटन के उद्देश्यों के बारे में पुनः आश्वस्त करने का प्रयास करेंगे तथा टैरिफ के लचीलेपन को प्रोजैक्ट करेंगे। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि भारत ऐसी कोई रियायत देने के मूड में नहीं है, जो उसकी घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग में कटौती करे, तथा अमेरिकन टैरिफ नीतियों की प्रस्तावित रियायतों पर आँखें मूँद कर भरोसा करे।

बीजिंग एकेडमी ऑफ सोशल साइन्सेज के एसोसिएट रिसर्च फैलो वांग पैंग ने कहा है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच के टैरिफ-जन्य तनाव

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अमेरिका के टैरिफ वॉर का मकसद है, अमेरिका में काम आने वाली ज्यादा से ज्यादा चीज़ें अमेरिका में ही निर्मित हों तथा अमेरिका विश्व का "मैन्युफैक्चरिंग हब" (औद्योगिक उत्पादन का केन्द्र) बने।
- दूसरी ओर भारत का "मेक इन इण्डिया" का सोच भी, हिन्दुस्तान में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने की दिशा को ही सही मानता है।
- अतः, उपराष्ट्रपति वैंस की भारत यात्रा एक गुडविल (सद्भावना यात्रा) तक ही सीमित रहेगी और कोई ठोस लाभ नहीं मिलेगा, भारत को "टैरिफ वॉर" में।

प्रजापति हत्याकांड में हरीश चौधरी का नाम?

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अप्रैल। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी का नाम सीबीआई कोर्ट की 32 पृष्ठ की रिपोर्ट में है। कमलेश प्रजापति के फर्जी एनकाउंटर में उनकी व उनके भाई मनीष चौधरी की भूमिका की जाँच की मांग की गई है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फर्ज़ी मुठभेड़ और प्रजापति की हत्या का केस सीबीआई को सौंपा था। सवाल यह है कि क्या यह गहलोत की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की आखिरी जीत है।

इसी सीबीआई कोर्ट ने इस प्रकरण में हरीश चौधरी, उनके भाई मनीष चौधरी और 2 आईपीएस अफसर सहित, 24 पुलिस अफसरों की भूमिका पर सवाल उठाए थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सीबीआई कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में हरीश के खिलाफ जाँच के आदेश दिये।